गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 262
दि. 23.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

खूंखार नक्सली अनल दा समेत 15 माओवादी ढेर, सरकार ने रखा था एक करोड़ का इनाम

(जीएनएस)। पश्चिम सिंहभूम के घने और दुर्गम सारंडा जंगल में गुरुवार को जो हुआ, वह झारखंड में दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता पतिराम मांझी उर्फ अनल दा समेत 15 माओवादियों का मारा जाना न केवल सुरक्षा बलों की बड़ी रणनीतिक सफलता है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि राज्य में माओवादी नेटवर्क अब अंतिम सांसें गिन रहा है। वर्षों से जिस अनल दा का नाम सुनकर पुलिस, प्रशासन और आम ग्रामीणों में डर का माहौल बन जाता था, वही अनल दा अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है।

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा जंगल लंबे समय से माओवादियों का मजबूत गढ़ रहा है। घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़, सीमित सड़कें और संचार के कमजोर साधन इस क्षेत्र को माओवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाते रहे हैं। इसी इलाके में सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने ऐसा प्रहार किया, जिसने माओवादी संगठन की रीढ़ तोड़ दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन में करीब 1500 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन यानी कोबरा की 209वीं बटालियन ने इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया। खुफिया एजेंसियों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर मंगलवार से ही सारंडा के विभिन्न इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। गुरुवार तड़के जब सुरक्षाबल किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुमड़ी और कुंभदिह गांव के आसपास जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी माओवादियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी।

माओवादियों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि सुरक्षाबल इतनी बड़ी संख्या में और इतनी सटीक योजना के साथ इलाके को घेर चुके हैं। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला और कई घंटों तक चली भीषण मुठभेड़ में 15 माओवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से अत्याधुनिक हथियार, इंसास और एसएलआर राइफलें, कार्बाइन, भारी मात्रा में गोलियां, विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई है, जो इस बात का संकेत है कि माओवादी किसी बड़े हमले की फिराक में थे। झारखंड पुलिस के आईजी (ऑपरेशन) माइकल राज एस ने बताया कि मुठभेड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और पूरे सारंडा आरक्षित वन क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया

गया है। भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद कर दिया गया है और अतिरिक्त बलों को मौके पर भेजा गया है। इलाके की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षाबल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान समाप्त होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

इस मुठभेड़ का सबसे बड़ा नाम है अनल दा। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला पतिराम मांझी उर्फ अनल दा उर्फ तूफान उर्फ रमेश, भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी का प्रमुख सदस्य था। वह संगठन का रणनीतिकार माना जाता था और कई बड़े नक्सली हमलों की योजना उसी के दिमाग की उपज रही है। 1987 से सक्रिय अनल दा ने झारखंड और बिहार के कई इलाकों में माओवादी संगठन की जड़ें मजबूत की थीं।

1987 से 2000 के बीच उसने पीरटांड़, टुंडी और तोपचांद क्षेत्रों में 'गोपाल दा' के नाम से संगठन का विस्तार किया। इस दौरान नक्सलियों ने ग्रामीण इलाकों में समानांतर शासन जैसी स्थिति बना ली थी। पुलिस की आवाजाही मुश्किल हो गई थी और आम ग्रामीण भय के साये में जीने को मजबूर थे। अनल दा की रणनीति यह थी कि जंगलों और पहाड़ी इलाकों को आधार बनाकर धीरे-धीरे संगठन को मजबूत किया जाए और फिर बड़े हमलों के जरिए सरकार और प्रशासन को चुनौती दी जाए। समय के साथ अनल दा माओवादी संगठन में और ऊपर पहुंचता गया। वह केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना और झारखंड में नक्सली गतिविधियों का प्रमुख चेहरा बन गया। उस पर कई बड़े हमलों, सुरक्षाबलों पर घात लगाकर किए गए हमलों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। इसी कारण झारखंड सरकार ने उस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था। हाल के वर्षों में सुरक्षाबलों ने झारखंड के कई इलाकों में माओवादियों की कमर तोड़ दी है। बुडा पहाड़, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और पारसनाथ जैसे इलाकों में माओवादी गतिविधियों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है। कोल्हान और सारंडा को माओवादियों का अंतिम गढ़ माना जा रहा था, लेकिन अब यहां भी सुरक्षाबलों की पकड़ मजबूत होती दिख रही है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ के महानिदेशक (ऑपरेशन) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा में एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के बचे हुए शीर्ष नेताओं के खिलाफ अंतिम चरण के अभियान का रोडमैप तैयार किया गया था। इस रणनीति का ही परिणाम माना जा रहा है कि अनल दा जैसे बड़े नक्सली नेता को मार गिराया गया।

इस ऑपरेशन के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में संतोष का माहौल है। अधिकारियों का मानना है कि अनल दा की मौत से माओवादी संगठन को नेतृत्व स्तर पर गहरा झटका लगा है, जिसकी भरपाई करना उसके लिए आसान नहीं होगा।

मुरी गंगा में डूबा बांग्लादेशी मालवाहक जहाज, मछुआरों की सतर्कता से टली बड़ी त्रासदी

(जीएनएस)। कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मुरी गंगा नदी में बुधवार को एक बांग्लादेशी मालवाहक जहाज के डूबने से हड़कंप मच गया। यह घटना देखते ही देखते एक बड़े हादसे का रूप ले सकती थी, लेकिन स्थानीय मछुआरों की सतर्कता और पुलिस की तत्परता से जहाज पर सवार सभी 12 लोगों की जान बचा ली गई। यह जहाज बांग्लादेश के खुलना बंदरगाह का था और बज बज से फ्लाई ऐश लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। नदी के बीच अचानक हुए इस हादसे ने एक बार फिर नदी परिवहन की चुनौतियों और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'एमवी तमजीद' नाम का यह मालवाहक जहाज जब मुरी गंगा नदी पार कर रहा था, उसी दौरान वह पानी के नीचे मौजूद एक रेत के टीले से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के मध्य हिस्से में बड़ा छेद हो गया और देखते ही देखते पानी जहाज के अंदर भरने लगा। नदी का बहाव तेज था और जहाज पर लदा भारी माल स्थिति को और भी गंभीर बना रहा था। कुछ ही पलों में जहाज असंतुलित हो गया और डूबने लगा। इस दौरान चालक दल के सभी सदस्य जहाज पर ही फंसे रह गए और उनके पास बचने का कोई तत्काल साधन नहीं था।

हादसे के समय नदी में मछली पकड़ रहे स्थानीय मछुआरों ने जब जहाज को डूबते देखा तो उन्होंने बिना समय गंवाए सागर पुलिस स्टेशन को सूचना दी। मछुआरों ने अपने स्तर पर भी मदद की कोशिश शुरू कर दी और छोटी-छोटी नौकाओं के जरिए जहाज के करीब पहुंचे। पुलिस को सूचना मिलते ही एक बचाव दल मौके पर रवाना किया गया। नदी का इलाका होने और मौसम में हल्की धुंध के कारण बचाव कार्य आसान नहीं था, लेकिन मछुआरों और पुलिस के आपसी समन्वय ने स्थिति को संभाल लिया। संयुक्त बचाव अभियान के दौरान एक-एक कर जहाज पर फंसे सभी 12 नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें से 11 नाविक बांग्लादेश के नागरिक हैं, जबकि एक अन्य चालक दल का सदस्य किसी अन्य देश का बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि किसी भी नाविक को गंभीर चोट नहीं आई। कुछ लोग घबराहट और ठंड के कारण असहज जरूर थे, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा के बाद सभी को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ठहराया है।

यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मुरी गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जलमार्ग व्यापार का एक अहम हिस्सा है। इस मार्ग से नियमित रूप से मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। फ्लाई ऐश जैसे औद्योगिक कचरे और अन्य सामान की ढुलाई के लिए इस जलमार्ग का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। ऐसे में इस तरह का हादसा दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते बचाव नहीं होता, तो यह हादसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप ले सकता था। प्रशासन अब इस बात की गहन जांच कर रहा है कि जहाज के डूबने की असली वजह क्या थी। प्रारंभिक अनुमान में कहा जा रहा है कि पानी के नीचे बने रेत के टीले से टकराव मुख्य कारण रहा, लेकिन यह भी जांच की जा रही है कि कहीं जहाज के नेविगेशन सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी। इसके अलावा कोहरे या खराब दृश्यता की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर्दियों के मौसम में इस इलाके में अक्सर धुंध छाई रहती है, जिससे नदी में चल रहे जहाजों के लिए रास्ता देख पाना मुश्किल हो जाता है।

इस हादसे के बाद नदी सुरक्षा और जलमार्ग प्रबंधन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी के तल में लगातार बदलाव होते रहते हैं और रेत के टीले बनना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में नियमित सर्वे और मैपिंग बेहद जरूरी हो जाती है। यदि समय-समय पर नदी की गहराई और मार्ग का आकलन किया जाए, तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। साथ ही, आधुनिक नेविगेशन उपकरणों और प्रशिक्षित चालक दल की भूमिका भी बेहद अहम होती है।

स्थानीय लोगों और मछुआरों की भूमिका की भी हर ओर सराहना हो रही है। यदि वे समय रहते पुलिस को सूचना न देते और खुद आगे बढ़कर मदद न करते, तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि इन मछुआरों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 12 लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आपदा की घड़ी में स्थानीय समुदाय कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फिलहाल डूबे हुए जहाज को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

समन मामले में केजरीवाल को राहत, लेकिन शराब नीति विवाद पर सियासत और जांच दोनों जारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली की एक अदालत से आए फैसले ने आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को तात्कालिक राहत जरूर दी है, लेकिन दिल्ली की कथित शराब नीति से जुड़े विवाद पर सियासी घमासान को खत्म करने के बजाय और तेज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर पेश न होने के आरोप में दायर वाद में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे 'सत्य की जीत' बताते हुए जश्न जैसा माहौल बनाया, जबकि भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए साफ किया कि यह राहत केवल एक तकनीकी और सीमित मामले तक है, न कि कथित शराब घोटाले से पूरी तरह बरी होने का प्रमाण। अदालत के इस फैसले का दायरा समझना जरूरी है। यह मामला सीधे तौर पर दिल्ली की शराब नीति या उसमें कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं था, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश न होने से संबंधित था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था और जब वे

पेश नहीं हुए तो इस आधार पर अदालत में वाद दायर किया गया। अदालत ने यह माना कि इस विशेष मामले में केजरीवाल को बरी किया जा सकता है। इसके बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर फैसले का स्वागत करते हुए 'सत्यमेव जयते' लिखा और इसे सत्य की जीत बताया। हालांकि, भाजपा ने तुरंत इस नैरेटिव को चुनौती दी। भाजपा नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर जनता में यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों से मुक्त हो गए हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। भाजपा के अनुसार, अदालत का फैसला केवल समन पर पेश न होने के मामले तक सीमित है और दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा मुख्य मामला अब भी जांच के दायरे में है। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों की जांच जारी है और आने वाले समय में इसमें और कानूनी तथा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

दिल्ली की शराब नीति को लेकर विवाद की शुरुआत वर्ष 2021-22 में हुई, जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। सरकार ने दावा किया कि यह नीति पारदर्शिता बढ़ाने, राजस्व में इजाफा करने और शराब माफिया के दबदबे को खत्म करने के लिए लाई गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सुधारवादी कदम बताया और कहा कि इससे सरकारी खजाने को फायदा होगा। लेकिन भाजपा ने शुरुआत से ही इस नीति पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि इसके जरिए निजी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। विवाद तब और गहरा गया जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 20 जुलाई 2022 को इस नीति में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं को देखते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ की गई या उन्हें समन भेजे गए। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए लगातार कई बार समन जारी किए। केजरीवाल का पक्ष रहा कि ये समन राजनीतिक बदले की भावना से जारी किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल ने कई मौकों पर कहा कि वे जांच से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन समन की वैधता और समय पर सवाल उठा रहे हैं। इसी विवाद के बीच समन पर पेश न होने को लेकर ईडी ने अदालत का रुख किया, जिस पर अब फैसला आया है।

फोन टैपिंग प्रकरण में के टी रामा राव से एसआईटी की अहम पूछताछ, सियासत में बढ़ा तनाव

(जीएनएस)। हैदराबाद में शुक्रवार को तेलंगाना की राजनीति एक बार फिर गरमा गई, जब बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के टी रामा राव से विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा पूछताछ किए जाने की तैयारी की गई। यह मामला पहले ही राज्य की राजनीति में भूचाल ला चुका है और अब इसमें शीर्ष नेताओं से पूछताछ होने के कारण राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी की यह पूछताछ पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित रूप से की गई फोन टैपिंग, खुफिया जानकारी के दुरुपयोग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने के आरोपों से जुड़ी है।

तेलंगाना पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की परत-दर-परत जांच कर रही है। जांच एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में किन परिस्थितियों में फोन टैपिंग की गई, किसके आदेश पर यह प्रक्रिया चली और इसमें किन-किन अधिकारियों व नेताओं की भूमिका रही। आरोप है कि उस समय सत्ता में बैठे लोगों के राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों, नौकरशाहों और यहां तक कि कुछ न्यायिक हस्तियों के फोन भी टैप किए गए। इन आरोपों के सामने आने के बाद यह मामला केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और निजता के अधिकार से भी जुड़ गया है। एसआईटी इससे पहले बीआरएस के वरिष्ठ नेता और विधायक टी हरीश राव से 20 जनवरी को पूछताछ कर चुकी है। उनकी पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आने की बात कही जा रही है, हालांकि जांच एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर विवरण साझा नहीं किया है। माना जा रहा है कि हरीश राव से पूछताछ के बाद जांच का दायरा और व्यापक हुआ, जिसके चलते अब के टी रामा राव को भी तलब किया गया है। के टी रामा राव न सिर्फ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बल्कि पिछली सरकार में वे एक प्रभावशाली मंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनकी भूमिका को लेकर एसआईटी विशेष रूप से गंभीरता से जांच कर रही है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि यह मामला केवल फोन टैपिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को मिटाने या नष्ट करने के प्रयासों की भी जांच हो रही है। आरोप है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से महत्वपूर्ण खुफिया डेटा डिलीट कर दिया गया, ताकि संभावित सबूत सामने न आ सकें। एसआईटी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये निर्देश किस स्तर से आए और इसमें कौन-कौन शामिल था। इसी कड़ी में के टी रामा राव से पूछताछ को बेहद अहम माना जा रहा है। बीआरएस की ओर से इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सत्ता में आने के बाद नई सरकार विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार और पुलिस का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच पूरी तरह निष्पक्ष व तथ्यों पर आधारित है। उनका दावा है कि फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोपों की गहन जांच जरूरी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नागरिकों की निजता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।

इस मामले ने तेलंगाना की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक ओर विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया कदम बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि के टी रामा राव से पूछताछ के बाद यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि इससे कई नए नाम और तथ्य सामने आने की संभावना है। आने वाले दिनों में इस जांच के नतीजे न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं।

लाल किला हमले के दोषी आतंकी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख, सरकार से जवाब तलब

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और संप्रभुता को झकझोर देने वाले वर्ष 2000 के लाल किला आतंकी हमले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अहम कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को इस हमले के दोषी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की ओर से दायर सुधारात्मक याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका उसकी मौत की सजा के खिलाफ दाखिल की गई है। अदालत के इस कदम के साथ ही एक बार फिर यह मामला कानूनी और संवैधानिक विमर्श के केंद्र में आ गया है, जिसमें आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों में सजा, न्याय प्रक्रिया और अंतिम कानूनी उपायों पर बहस स्वाभाविक रूप से तेज हो गई है। मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जो नवंबर 2022 में सुनाया गया था। उस समय अदालत ने उसकी समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा था। अब उसने सुधारात्मक याचिका दाखिल कर अंतिम कानूनी रास्ते का सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, ताकि याचिका में उठाए गए तर्कों और तथ्यों पर राज्य का पक्ष सामने आ सके। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ के समक्ष हुई, जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि सुधारात्मक याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सरकार की प्रतिक्रिया आवश्यक है। लाल किला हमला भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाता है। 22 दिसंबर 2000 को हुए इस आतंकी हमले में हथियारबंद आतंकियों ने ऐतिहासिक लाल किले के

भीतर घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। यह हमला न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती था, बल्कि देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। इस हमले के बाद व्यापक जांच हुई और अंततः मोहम्मद आरिफ को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख शुरू से ही बेहद सख्त रहा है। वर्ष 2014 में अदालत ने आरिफ की फांसी पर अस्थायी रोक जरूर लगाई थी, लेकिन यह रोक कानूनी प्रक्रिया और विकसित हो रहे न्यायिक मानकों के तहत दी गई थी। 2016 में संविधान पीठ के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद मौत की सजा से जुड़े मामलों में समीक्षा याचिकाओं को खुली अदालत में सुनने का प्रावधान किया गया, जिससे दोषियों को अंतिम अवसर मिल सके कि वे अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकें। इसी प्रक्रिया के तहत आरिफ की समीक्षा याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद जैसे अपराध किसी भी सूरत में नरमी के पात्र नहीं हो सकते।

अपने 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। अदालत ने कहा था कि ऐसे अपराध समाज को डराने, राज्य की नींव को कमजोर करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसलिए इन मामलों में सजा तय करते समय अत्यंत कठोर दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि आरिफ के अपराध 'दुर्लभतम से दुर्लभ' की श्रेणी में आते हैं, जहां मौत की सजा ही उपयुक्त मानी जा सकती है। अब सुधारात्मक याचिका के जरिए आरिफ ने अंतिम संवैधानिक उपाय का सहारा लिया है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधारात्मक याचिका को अत्यंत असाधारण स्थिति में स्वीकार किया जाता है, जब यह साबित हो कि न्याय प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि हुई है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। ऐसे मामलों में अदालत बहुत सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, यह माना जा रहा है कि अदालत पूर्व में दिए गए अपने फैसलों और आतंकवाद पर अपनाए गए सख्त रुख से आसानी से पीछे नहीं हटेगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश में आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर चर्चा को तेज कर दिया है। एक ओर मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम अवसर देने की बात होती है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और शहीदों के प्रति न्याय की भावना भी उतनी ही प्रबल है।

पश्चिपश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्य के बीच स्पेशल ट्रेनो को चलाइ जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियाँ	प्रस्थान	आगमन
09005	बांद्रा टर्मिनस - भिवानी (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	28.01.2026 से 25.02.2026	11:00 बजे (बुधवार)	13:00 बजे (दुसरे दिन)
09006	भिवानी - बांद्रा टर्मिनस (सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल)	29.01.2026 से 26.02.2026	14:35 बजे (गुरुवार)	16:10 बजे (दुसरे दिन)

होल्टः बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, कोसली और चरखी दादरी स्टेशन दोनों दिशाओं में।

संरचना: AC 2-टियर, AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

09035	बांद्रा टर्मिनस - उधना (द्वि साप्ताहिक स्पेशयल)	30.01.2026 से 28.02.2026	09:00 बजे (शुक्र और शनि)	15:05 बजे (उसी दिन)
09036	उधना - बांद्रा टर्मिनस (द्वि साप्ताहिक स्पेशयल)	29.01.2026 से 27.02.2026	15:45 बजे (गुरु और शुक्र)	21:35 बजे (उसी दिन)

होल्टः अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वंगांव, दहानू रोड, घोलवड, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भिलाड, करमबेली, वापी, वलसाड, बिलिमोरा और नवसारी स्टेशन दोनों दिशाओं में।
ट्रेन नंबर 09035 का एक अतिरिक्त स्टॉप भायंदर में होगा और ट्रेन नंबर 09036 के अतिरिक्त स्टॉप अतुल, पारडी और उदवाड़ा में होंगे।

संरचना: स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

09561	बांद्रा टर्मिनस - ओखा (साप्ताहिक स्पेशल)	28.01.2026 से 25.02.2026	05:50 बजे (बुधवार)	22:50 बजे (उसी दिन)
09562	ओखा - बांद्रा टर्मिनस (साप्ताहिक स्पेशल)	27.01.2026 से 24.02.2026	10:20 बजे (मंगलवार)	04:20 बजे (दुसरे दिन)

होल्टः बोरीवली, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेंद्र नगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खंभालिया और द्वारका स्टेशन दोनों दिशाओं में।
संरचना: कोच: AC 2-टियर, AC 3-टियर, AC 3-टियर इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09005, 09035, 09036, 09561 और 09562 के लिए बुकिंग सभी PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर खुली है। ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाइ जाएगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें और हमें फॉलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ लाएँ।

संपादकीय

दोस्ती की लिखावट

निस्संदेह डिजिटल दौर के नशे में डूबी पीढ़ी वास्तविक रिश्तों से दूर होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर छात्रों की लिखने की आदत भी छूटती जा रही है। लेखन हमारी मौलिक व सार्थक अभिव्यक्ति है और सेहत से भी जुड़ा है। पुरानी कहावत है—जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता। कमोबेश मौजूदा दौर में हकीकत यही है कि जिनके सोशल मीडिया में हजारों-लाखों मित्र व फॉलोवर होते हैं वे निजी जीवन में नितांत एकाकी होते हैं। यह घातक प्रवृत्ति बच्चों में भी तेजी से घर कर रही है। लेखन में हमारी उंगलियों के पोर इस्तेमाल होते हैं, जिनके सिरे हमारे विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य से गहरे तक जुड़े रहते हैं। कलम या पेन से लेखन हमारे बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। लेकिन आज मोबाइल व कंप्यूटर, लेपटॉप व टैबलेट के दौर में बच्चे लेखन से दूर होकर खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इस संकट को महसूस करते हुए सीबीएसई ने छात्रों को मित्रों से जुड़ाव व उनकी लेखन कला को निखारने के लिए अभिनव पहल की है। बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 'इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपीटिशन-2026' आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाले छात्र को पचास हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही विजेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी दिया जाएगा। छात्रों को जो पत्र लिखने का विषय दिया गया है वह मौजूदा हालात में बेहद रोचक व उपयोगी है। छात्र को अपने दोस्त को पत्र लिखना है कि मौजूदा डिजिटल दौर में लोगों का आपसी जुड़ाव व बातचीत क्यों जरूरी है। दरअसल, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की सोच को विस्तार देना और उनकी लेखन कला को निखारना है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रतिभागी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने पर छात्र को स्विट्ज़रलैंड के बर्न स्थित यूपीए हेड क्वार्टर का दौरा करने का अवसर मिल सकता है। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी नौ से पंद्रह साल के ही होने चाहिए। वे अपनी एंट्री अंग्रेजी व हिंदी में भी दे सकते हैं। प्रतिभागी अपने स्कूल के माध्यम से ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों में लिखने की घटती प्रवृत्ति के दौर में यह एक रचनात्मक प्रयास है। दरअसल, लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते बच्चे न केवल रचनात्मक लेखन से वंचित हो रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों से भी कटते जा रहे हैं, जिसका असर उनकी याददाश्त व सृजन क्षमता पर भी पड़ रहा है। एक समय था बच्चे डायरी लेखन व स्कूलों में कविता व लेख लिखने को खासे उत्सुक होते थे। दोस्तों के साथ खेल के मैदान और घर पर खेलना उन्हें शारीरिक व मानसिक स्तर पर स्वस्थ रखता था। लेकिन आज बच्चे ऑनलाइन खेलों में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने असली दोस्तों का ख्याल ही नहीं रहता। वे जीवन की वास्तविक चुनौतियों से दूर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज शारीरिक सक्रियता के अभाव के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही वयस्कों जैसे रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। ये रोग शारीरिक भी हैं और मानसिक भी हैं। छात्र अपना बचपन स्वाभाविक रूप से नहीं जी पा रहे हैं। सही मायनों में वे समय से पहले वयस्क होते जा रहे हैं। एक समय बच्चों की लेखन क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। परीक्षा में बाकायदा सुंदर लेखन के अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। लेकिन आज बच्चे इंटरनेट पर उपलब्ध शॉर्टकट के जरिये हर परीक्षा पास करना चाहते हैं। कट-पेस्ट संस्कृति ने उनकी मौलिक सोच व सृजनात्मकता को ग्रहण लगा दिया। अक्सर छात्र प्रतियोगात्मक परीक्षाओं व लेखन प्रतिस्पर्धाओं में ऑनलाइन माध्यमों व इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को हेर-फेर के साथ प्रस्तुत करते देखे जा रहे हैं, जो उन्हें व्यावहारिक जीवन की प्रतिस्पर्धा में कमजोर बनाता है। ऐसे में सीबीएसई व पोस्टल विभाग की पहल अनुकरणीय व प्रशंसनीय है।

विश्व व्यवस्था में रणनीतिक उलझाव पर बदलता नजरिया

“ रणनीतिक अस्पष्टता कभी वक्त निकालने का तरीका था जिससे तनाव घटाया जा सके। ताकि इतिहास अपना काम कर सके। यह स्थायित्व में भी मददगार थी। लेकिन मौजूदा बिखरावपूर्ण विश्व व्यवस्था में, यह फैसले टालने, जवाबदेही बगैर सहनशक्ति परखने व तथ्य बदलने का जरिया है। यह अस्पष्टता अचानक विफल नहीं हुई बल्कि जानबूझकर की गयी।

दशकों तक, रणनीतिक अस्पष्टता को समझदारी की तरह लिया जाता था, समय निकालने का तरीका, तनाव घटाएं और इतिहास को अपना काम करने दें। एक अधिक संतुलित दुनिया में, इसने स्थायित्व बनाने का काम किया। मौजूदा बिखरावपूर्ण विश्व व्यवस्था में, यह फैसला टालने, जवाबदेही बगैर सहनशक्ति परखने व तथ्य बदलने का जरिया है। जो उपाय कभी शांति कायम रखता था, आज अनिश्चितता बढ़ा रहा है। परिणाम है नियंत्रित विचलन। अस्पष्टता अचानक विफल नहीं हुई; जानबूझकर की गयी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने शनैः-शनैः संयम को चुप्पी मानना सीख लिया। मुश्किल सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए गये, सीमाएं अस्पष्ट और समयसीमा अनिर्धारित बनी रहीं। असमान महत्वाकांक्षा और अवसरवादी संशोधनवाद के युग में, अस्पष्टता सुरक्षा कवच की बजाय बोझ बन गई, जिसका दोहन वे करते हैं जिन्हें देरी करते जाने से फायदा है और भुगतना उन्हें पड़ता है जो विश्व व्यवस्था का पालन करने पर निर्भर रहते हैं। रणनीतिक अस्पष्टता की शुरुआत टालमटोल के तौर पर नहीं हुई थी। इसका मकसद था इरादे परखना और तालमेल बनने देना। यह कारगर रहा क्योंकि यह पारस्परिक आधार पर था और इसमें संतुलन शामिल था। समय के साथ, दोहराव ने इसे खोखला कर डाला। एक अस्थायी उपाय वह प्रवृत्ति बन गया;जिसका उद्देश्य नीयत स्पष्ट करना था, वह यथास्थिति की धीरे-धीरे, हिसाब-किताब लगाकर समाप्ति का तरीका बन गया।

जब अस्पष्टता असमानता हो जाए : अनिर्धारित सीमाओं से इतर इसकी मिसाल कहीं इतनी साफ दिखाई नहीं देती। बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में, नीति का मोल विरल हवा और जमी बर्फ में मापा जाता है। सबसे पहले नागरिकों को भुगतना पड़ता है, मसलन,कोई चरवाहा किसी रोज पाए कि एक गैर-मान्यताप्राप्त बाड़बंदी ने पीढ़ियों पुरानी उसकी चरागाह छीन ली या जब कोई ग्रामीण पाए कि पुरखों से चला रहा उसके क्षेत्र का नक्शा रात में खामोश सैनिक गश्त

से पुनर्निर्धारित कर दिया गया। दूर समुद्र में , मछुआरों का यह पाना कि उनकी आजीविका रातोंरात अपराध बन गयी, इसलिए नहीं कि नक्शों की लकीरें सार्वजनिक रूप से पुनः खींची गईं, बल्कि इसलिए कि वे जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दी थी।

ऐसी सीमाओं पर, सैनिक अनिश्चितता को जीवन का अंग मानकर जीते हैं। वे उसी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन पर चलते हैं, मामला निबटा देने की बजाए संयम बरतते हैं। जब अस्पष्टता पककर टकराव में बदल जाती है, तब उन्हें राजधानियों में अनिर्णय से पैदा जोखिम संभालने के लिए मानव बारूदी सुरंगों के रूप में आगे कर दिया जाता है।

लीक बदलने की लोकतांत्रिक कीमत : लंबे समय तक जारी अस्पष्टता की कीमत समान रूप से नहीं झेलनी पड़ती। लोकतंत्र बहसों और जवाबदेही के जरिये अनिश्चितता को जज़्ब करते हैं। संशोधनवादी व्यवस्थाएं छद्म रूप से अस्पष्टता चलाती हैं। असमान संदर्भों में, अस्पष्टता सबसे मज़बूत पक्ष का भरोसेमंद साथ निभाती है। लीक में बदलाव असमान लागत लागू करता है और औपचारिक पसंद के बगैर, अंश-वार बदलाव बनाता है। ऐसी स्थितियों में, स्पष्टता टकराव नहीं बढ़ाती ; यह लोकतांत्रिक स्वच्छता है।

नियम कौन लिखता है : जब लोकतंत्र प्रारूप बनाने को टालते हैं, तो वे मूल स्वरूप खो देते हैं। नियम सहमति से नहीं, बल्कि बारंबार प्रक्रिया से बदलते हैं। अस्पष्टता विकल्पों का तबतक क्षरण करती जाती है जबतक कि सिर्फ़ एक ही बचे। एक सदी से भी पहले, लॉर्ड कर्ज़न ने पाया था कि सीमाओं को तय करने के बजाय उन्हें अनिर्धारित छोड़ देने से लाभ ज़्यादा होता है। उनकी यह अंतदृष्टि फायदा उठाने की गर्ज से थी। अस्पष्टता उस हित में है जो नक्शे को परिवर्तनीय और वक्त को हथियार की तरह बरतता है। समय सीमाओं का टकराव -2035 और 2047 : वह तर्क अब मद्धिम पड़ रहे वापसी बिंदु पर पहुंच चुका है। स्थिरता अब अनकही बातों पर और निर्भर नहीं रह सकती; यह योजनाबद्ध होनी चाहिए। जल्दबाज़ी तारीखों के टकराव से चालित है। चीन ने वर्ष 2035 को राष्ट्रीय कायाकल्प की समय-सीमा तय किया है। जबकि भारत का संकल्प साल 2047 तक है, जोकि आज़ादी का शताब्दी वर्ष है। बीच के दशकों को दूसरे की समयसीमा के हवाले करके कोई भी एक पक्ष ताकत का सभ्यतागत मील पत्थर हासिल नहीं कर सकता। जब एक पक्ष दशकों की योजना बना रहा हो और दूसरे की प्रतिक्रिया टुकड़ों में हो, तो अस्पष्टता तटस्थ नहीं रहती; यह महत्वाकांक्षा घटाने वाली बन जाती है।

समय अब क्यों मायने रखता है : योजनाबंदी को समयबद्ध अनुशासन की जरूरत होती है। समय सीमा वाली रूपरेखा टाल-मटोल के फायदों को उलट देती है। एक बार जब सीमा व समय तय हो जाए, तब संयम को औचित्य की और अधिक जरूरत नहीं रहती; उल्लंघन को पड़ती है। व्यावहारिक रूप से, यह तर्क इशारा करता है एक दीर्घ-कालिक,समय-सीमाबद्ध, महीनों में नहीं बल्कि दशकों में मापी जाने वाली रूपरेखा, वह जो समस्या के निबटारे में देरी वाले यथास्थिति उपाय को ठंडे बस्ते में डाल देने वाली, अधिक संतुलित घड़ी हो। 15 से 20 साल वाला क्षितिज रखना स्थायित्व को रियायत नहीं है; यह संरचना के साथ धैर्य को पुष्ट करना है। यह संवाद की पूर्व-बंदी या एकतरफा बदलावों को वैधता दिए बगैर, अस्पष्टता को दायित्व में और टालमटोल को जवाबदेही में रूपांतरित करना है। एक तयशुदा अवधि के लिए यथास्थिति बनाना बड़े लाभार्थी को उसके फायदे से वंचित करता है और शांत रहकर गतिविधि करने की बजाय जानबूझकर किए काम से संशोधनवाद को सतह पर आने पर मजबूर करता है। समय, जिसे कभी शक्तिशाली पक्ष हथियार की तरह बरतते रहे, तब एक बाधा बन जाएगा। या तो धैर्य महत्वाकांक्षा में देरी करवा देगा या फिर उल्लंघन इरादे को उजागर कर देगा।

रूपरेखा बनाना टकराव वृद्धि नहीं : यह एक ऐलान है। सोचसमझकर किया गया वह कार्य जिसके जरिये एक लोकतंत्र स्पष्ट व सरेआम ऐलान करता है कि अब किस मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी, किस की पुनर्समीक्षा की जाएगी, और वह क्या है जिसके परिणाम झेलने होंगे। प्रारूप बनाने का अभिप्राय अपना रुख सख्त बनाना नहीं ; यह नैतिक पलायन को समाप्त करना है जिसका पोषण अस्पष्टता करती है।

संयम से जिम्मेदारी तक : एक समयबद्ध प्रारूप शांति को तजता नहीं, जिम्मेदारी बहाल करता है। जब सीमाएं खींच दी जाएं व वक्त तय किया जाए, तब संयम को बहाने की और जरूरत नहीं रहती। नैतिकता का बोझ निर्णायक रूप से बदल जाता है, उस राज्य पर नहीं होता, जो अपनी लीक पर कायम है, बल्कि उस पर जो उल्लंघन करे। स्पष्टता उकसावा नहीं, जबावदेही है।

रणनीतिक प्रतीक्षा का अंत : कभी अस्पष्टता संतुलन के लिए काम की चीज़ थी। आज, यह उन लोगों का फायदा करती है जो मामला टालने से लाभ लेते हैं। रूपरेखा फिर से बनाने का मतलब टकराव चुनना नहीं;यह खुद की रूपरेखा बनाने की बात है। जो सभ्यताएं अपनी शर्तों को परिभाषित करने से इंकार करें, वे शांति सहेजकर नहीं रख पातीं;वे अपने भविष्य दूसरों के हवाले कर देती हैं। व्यावहारिक रूप से, ऐसे प्रारूप का स्वरूप है एक कूटनीतिक ठहराव, एक समयबद्ध यथास्थिति कायम रखना या तय अंतराल पर घोषित दायरे की पुनर्समीक्षा,जो संयम को धैर्य की मुद्रा से दायित्व के प्रारूप में बदल दे।

संयम अपना नैतिक अधिकार तब खो देता है जब वह ज़बरदस्ती चलाए। संवाद अपनी आत्मा तब खो देता है जब वह एकतरफ़ा फायदे को छिपाने वाला बन जाए। टालमटोल करते जाना अब सुरक्षा पाने का उपाय नहीं रहा; यह तो केवल जोखिम को श्रृंखला में निचली ओर धकेलना है, किसी चरवाहे, गश्ती दल या सैनिक पर। सुन त्ज़ू ने अस्पष्टता को धोखाधड़ी से जोड़ा था। चाणक्य ने चेताया था कि देरी करने से राज्य हाथ से निकल जाता है। क्लॉज़विट्ज़ हमें याद दिलाते हैं कि हिचकिचाहट दुश्मन को पहल का मौका दे देती है। रणनीतिक इंतज़ार का युग बीत चुका है। आगे जो कुछ भी होगा, या तो योजनाबद्ध ढंग से बनेगा या खुद ही खो जाएगा।

प्रेरणा

दायित्व से जन्मी मानवता

इतिहास में अनेक युद्ध हुए, अनेक वीरों के नाम दर्ज हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए मानवता की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ लड़ीं। क्रीमिया युद्ध के समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कार्य उसी श्रेणी में आता है। वह दौर केवल सैनिक टकराव का नहीं था, बल्कि मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था। युद्धभूमि पर घायल सैनिकों को बचाने के लिए जो अस्पताल बनाए गए थे, वही उनके लिए मृत्युस्थल बनते जा रहे थे। गंदगी, संक्रमण, अव्यवस्था और उदासीनता ने चिकित्सा व्यवस्था को लगभग निष्क्रिय कर दिया था। सरकार और सैन्य अधिकारी इन हालात को युद्ध की अनिवार्य कीमत मानकर स्वीकार कर चुके थे। यही स्वीकार्यता सबसे बड़ा संकट थी, क्योंकि जहाँ समस्या को नियति मान लिया जाए, वहाँ समाधान की संभावना समाप्त हो जाती है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल जब वहाँ पहुँचीं, तो उन्होंने सबसे पहले इसी सोच को चुनौती दी। उन्होंने देखा कि घायल सैनिक केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी टूट चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी की जिम्मेदारी नहीं हैं। गंदे फर्श पर पड़े बिस्तर, बदबू से भरे कमरे, साफ पानी का अभाव और अनियमित भोजन—ये सब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देने के लिए पर्याप्त थे। उस समय चिकित्सा विज्ञान सीमित था, लेकिन स्वच्छता और व्यवस्था जैसी मूलभूत बातें अपनाई जा सकती थीं। फ्लोरेंस ने समझ लिया कि यदि इन बुनियादी बातों को ठीक कर दिया जाए, तो अनगिनत जानें बच सकती हैं।

उन्होंने किसी पद या अधिकार के भरोसे नहीं, बल्कि अपने संकल्प के बल पर काम शुरू किया। रात में दीपक लेकर वार्डों में घूमना केवल एक भावनात्मक दृश्य नहीं था, बल्कि यह सैनिकों के लिए यह संदेश था कि कोई है जो उन्हें देख रहा है, सुन रहा है और उनके दर्द को अपना मान रहा है। उस दीपक की रोशनी में सैनिकों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे केवल संख्या नहीं, मनुष्य हैं। लेकिन फ्लोरेंस की करुणा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। नालियों की सफाई करवाई गई, हवादार कमरों की व्यवस्था की गई, बिस्तरों को नियमित रूप से बदला जाने लगा और भोजन की गुणवत्ता सुधारी गई। उस समय ये कदम साधारण नहीं, बल्कि क्रांतिकारी माने जाते थे। इस परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। कई अधिकारियों को लगता था कि युद्ध के बीच ऐसी व्यवस्था अव्यावहारिक है। कुछ को उनका अनुशासन कठोर प्रतीत होता था। लेकिन फ्लोरेंस ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनके लिए सेवा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अनुशासन करुणा का विरोधी नहीं, बल्कि उसका आधार है। बिना अनुशासन के करुणा बिखर जाती है और बिना करुणा के अनुशासन क्रूर बन जाता है। धीरे-धीरे परिणाम सामने आने लगे। मृत्यु दर में आश्चर्यजनक कमी आई। संक्रमण का प्रसार थमने लगा। सैनिकों का मनोबल बढ़ा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन मूल्यवान है। अस्पताल, जो पहले भय और मृत्यु के प्रतीक थे, अब उपचार और आशा के केंद्र बनने लगे। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, व्यवस्था और संवेदना के संतुलन से संभव हुआ। जो अधिकारी पहले फ्लोरेंस को अव्यावहारिक मानते थे, वही अब उनके निर्णयों का अनुसरण करने लगे।

एक बार उनसे पूछा गया कि वे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी थकती क्यों नहीं। उनका उत्तर साधारण शब्दों में गहरी सच्चाई कह गया। उन्होंने कहा कि जब किसी का दर्द आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, तब थकान स्वयं पीछे हट जाती है। इस विचार में सेवा का पूरा दर्शन समाया हुआ है। जब मनुष्य किसी कार्य को केवल नौकरी या दायित्व नहीं, बल्कि अपना उत्तरदायित्व मान लेता है, तब उसकी सीमाएँ विस्तृत हो जाती हैं। तब सेवा बोझ नहीं, साधना बन जाती है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में हम सेवा की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर उसे भावनात्मक सहानुभूति तक सीमित कर देते हैं। हम दुख देखकर संवेदना प्रकट करते हैं, पर व्यवस्था सुधारने, कठिन निर्णय लेने और अनुशासन लागू करने से बचते हैं। दूसरी ओर, कई जगह नियम और प्रक्रियाएँ तो हैं, लेकिन उनमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। दोनों ही स्थितियाँ अधूरी हैं। सच्ची सेवा वहीं संभव है, जहाँ करुणा और अनुशासन एक-दूसरे के पूरक बनें। यह सिद्धांत केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, प्रशासन, परिवार और समाज—हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। एक शिक्षक जो छात्रों से प्रेम करता है, लेकिन उन्हें अनुशासन नहीं सिखाता, वह उनके भविष्य के साथ अन्याय करता है। वहीं जो केवल नियमों पर ज़ोर देता है और संवेदना को भूल जाता है, वह भय तो पैदा कर सकता है, प्रेरणा नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन से यह संतुलन सिखाया। उनकी विरासत केवल क्रीमिया युद्ध तक सीमित नहीं रही। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित, संगठित और उत्तरदायी पेशा बनाया। उन्होंने यह साबित किया कि सेवा कोई छोटा या गौण कार्य नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की रीढ़ है। उनका दीपक आज भी प्रतीक है—उस चेतना का जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। हर वह व्यक्ति जो बिना दिखावे के जिम्मेदारी निभाता है, उसी दीपक की लौ को आगे बढ़ाता है। अंततः फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बड़े परिवर्तन अक्सर बड़े नारों से नहीं, बल्कि छोटे, लगातार किए गए सही कार्यों से होते हैं। साफ वातावरण, नियमित देखभाल और मानवीय दृष्टि—ये साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से असाधारण परिणाम निकलते हैं। जब सेवा दायित्व बन जाती है और करुणा अनुशासन के साथ चलती है, तब मानवता केवल जीवित नहीं रहती, बल्कि विकसित होती है। यही दायित्व से जन्मी मानवता का सच्चा अर्थ है।

Trump ने ग्रीनलैंड कब्जाया तो खुश क्यों होंगे पुतिन? वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

अगर लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, एक यहां पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े ही है। राहत इंदौरी का मशहूर शेर है। पिछले साल अमेरिकी की सत्ता संभालने के साथ ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के जरिए सभी को चौंका रहे हैं। ट्रंप सवेरे कुछ बोलते है, शाम को कुछ सोचते है और रात को कुछ और ही करते है। उनके सोचने, समझने और कहने व करने में कोई कनेक्शन अमूमन होता नहीं है। ट्रंप ने जब वेनेजुएला जैसे देश पर स्ट्राइक कर उसके राष्ट्रपति को पत्नी सहित बेड़ियों में जकड़कर अपने देश में ले आए तो उस वक्त यूरोप ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं और वो खामोश कहा बैठने वाले थे। उनका अगला टारगेट ग्रीनलैंड बना। रोज उस पर नए नए बयान सामने आने लगे। यूरोप सहित नाटो का ट्रंप कभी मजाक बनाते तो कभी धमकाते नजर आए। लेकिन इस बार यूरोपिय देशों ने हिम्मत जुटाकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के खिलाफ खिलाफत का बिगूल फूंक दिया। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की चाह को लेकर नाटो में लड़ाई छिड़ गई है। फ्रांस जैसे यूरोपियन नाटो मेंबर्स इससे नाराज हो गए हैं। ग्रीनलैंड की स्वायत्ता को लेकर यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और डेनमार्क ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज किया था। ईयू मेंबर्स जैसे यूके, नॉर्वे और कनाडा ने अमेरिका की धमकियों की निंदा की है। ऑपरेशन आर्कटिक सिक्योरिटी के अंतर्गत आर्मी पर्सनल भी डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन आपने वो पुरानी कहावत तो खूब सुनी होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले जाता है। यूरोप और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का सीधा फायदा रूस को होगा। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन में अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान सोवियत यूनियन में दशकों तक अमेरिका डिसोल्यूशन प्रोग्राम चला रहा था और फिर टूट गया था। अमेरिका और ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रूस ने भी इस मामले में अपनी एंट्री ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की कोशिशों ने एक ओर जहां डेनमार्क को असमंजस में डाल दिया है और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की एकजुटता को भी झकझोर दिया है वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है कि ग्रीनलैंड के साथ क्या होता है। उनका यह बयान टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूं तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को हमेशा एक उपनिवेश की तरह माना है और उसके प्रति क्रूर नहीं, तो काफी कठोर रवैया तो अपनाया ही है लेकिन यह बिल्कुल अलग मामला है और मुझे संदेह है कि अभी किसी की इसमें रुचि होगी। पुतिन ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। मुझे लगता है कि वे इसे आपस में सुलझा लेंगे। उन्होंने जिक्र किया कि 1917 में डेनमार्क ने इस द्वीप समूह को अमेरिका को बेच दिया था। पुतिन ने इस बात का भी जिक्र किया कि 1867 में रूस ने अलास्का को 72 लाख अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को बेच दिया था।

अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव को रूस अपने लिए एक मौके के रूप में देख रहा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की योजनाओं के साथ मॉस्को का सहयोग एक सोच-समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद पश्चिमी देशों की एकता को कमजोर करना और अमेरिका का ध्यान दूसरी दिशाओं में उलझाए रखना है। यह रणनीति कुछ हद तक सफल भी होती दिख रही है। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों के कड़े विरोध के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुले तौर पर तारीफ की। उन्होंने शी को “अद्भुत व्यक्ति” बताया और कहा कि उन्होंने “बेहद शानदार काम” किए हैं और वे “दुनिया भर में सम्मानित” हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी दोहराया कि उनके संबंध शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। इसी सप्ताह जब ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिशों को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ा, तो रूस में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। रूसी अधिकारियों, सरकारी समर्थन वाले मीडिया और क्रेमलिन समर्थक ब्लॉगर्स ने इस पर खुशी, तंज और कुछ हद तक सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने ट्रंप के कदम को ऐतिहासिक बताया, जबकि दूसरों का कहना था कि इससे यूरोपीय संघ और नाटो कमजोर होते हैं, जो रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इससे पश्चिमी देशों का ध्यान रूस–यूक्रेन युद्ध से भी कुछ हद तक हटता है, जो मॉस्को के हित में जाता है।

ग्रीनलैंड पर धमकी के बीच चीन ने कहा कि अपने हित साधने के लिए अमेरिका 'चीनी खतरे' को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद करे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों पर कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। ने भी कहा कि ग्रीनलैंड के आसपास की 'गंभीर भू-राजनीतिक स्थिति' रूस पर हमारी नजर है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ किया कि ग्रीनलैंड के मामलो में दखल देने में रूस की दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका भी जानता है कि रूस की ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोई योजना नही है। लावरोव ने यह भी कहा कि हमारे विचार से ग्रीनलैंड डेनमार्क का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है। यह न तो नॉर्वे का प्राकृतिक हिस्सा था और न ही डेनमार्क का। यह औपनिवेशिक जीत का हिस्सा है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए रूस और चीन को खतरा बता रहे हैं। इसको लेकर वहां के विदेश मंत्री सरगे लावो ने बयान दिया है और ग्रीनलैंड को लेकर बड़ी बात कही है। 20 जनवरी 2026 को लावरोव ने मास्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस का ग्रीनलैंड के मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है।

अभियान

आस्था की अग्नि में सिद्ध होती शक्ति

भारत की आध्यात्मिक भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं, जहाँ पहुँचकर तर्क स्वतः मौन हो जाता है और अनुभव बोलने लगता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तंत्र, साधना और रहस्य का जीवंत केंद्र है। इसे देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ सृष्टि की रचनात्मक शक्ति का वास है। मां कामाख्या को इच्छा पूर्ति की देवी माना जाता है और तांत्रिक परंपरा में उनका विशेष स्थान है। इसी मंदिर से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है, जो देखने वालों को चकित कर देती है और जिसे समझने की कोशिश में विज्ञान भी ठहर-सा जाता है। मां कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी और चर्चित परंपराओं में से एक है यहां का विशेष प्रसाद, जिसे 'महानिर्मल्य' कहा जाता है। यह प्रसाद न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है, बल्कि इसकी विधि इतनी अद्भुत है कि इसे देखकर श्रद्धालुओं के मन में विस्मय और श्रद्धा एक साथ उमड़ पड़ते हैं। इस प्रसाद को तैयार करने और वितरित करने की प्रक्रिया साधारण नहीं है। इसके लिए मंदिर के पुजारी खौलते हुए तेल या घी में बिना किसी सुरक्षा के अपना हाथ डालते हैं और उसी में से प्रसाद निकालकर भक्तों को वितरित करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुजारी के हाथ पर न तो जलन के निशान पड़ते हैं, न छाले बनते हैं और न ही कोई घाव दिखाई देता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस बर्तन में घी या तेल होता है, वह सचमुच खौल रहा होता है। उसमें बुलबुले उठते साफ दिखाई देते हैं। सामान्य परिस्थिति में उस तापमान पर किसी भी व्यक्ति का हाथ एक क्षण में झुलस सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यह दृश्य पहली बार देखने वाले व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय होता है। कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कई इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं, तो कुछ इसे गहन साधना का परिणाम बताते हैं। मंदिर से जुड़े लोगों और श्रद्धालुओं का दृढ़ विश्वास है कि यह सब मां कामाख्या की कृपा से ही संभव होता है।

यह माना जाता है कि इस विशेष कार्य के लिए हर कोई पुजारी चयनित नहीं होता। जो पुजारी इस सेवा के लिए चुने जाते हैं, वे लंबे समय तक कठोर तपस्या, व्रत, संयम और साधना करते हैं। उनका जीवन अत्यंत अनुशासित होता है। वे सात्त्विक आहार लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से दूरी बनाए रखते हैं। तांत्रिक परंपरा में यह माना जाता है कि जब साधक पूर्ण रूप से अपने अहंकार का त्याग कर देता है और स्वयं को देवी की शक्ति के प्रति समर्पित कर देता है, तब वह साधक और शक्ति के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। इसी अवस्था में ऐसे अलौकिक कार्य संभव हो पाते हैं।

मां कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ साधना का स्वरूप सामान्य भक्ति से अलग है। यहाँ शक्ति की आराधना होती है, सृजन की ऊर्जा की उपासना होती है। यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि जीवन केवल त्याग नहीं, बल्कि सृजन भी है। इसी कारण यहां की परंपराएं भी सामान्य मंदिरों से भिन्न हैं। महानिर्मल्य का प्रसाद उसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अग्नि में भी शीतलता का अनुभव करवा देती है और साधक को भय से मुक्त कर देती है।

श्रद्धालुओं का मानना है कि जब पुजारी मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा के बाद खौलते तेल में हाथ डालते हैं, तो उस समय वे स्वयं नहीं होते, बल्कि मां कामाख्या की शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। उस क्षण उनका शरीर सामान्य मानवीय नियमों से परे हो जाता है। अग्नि, जो सामान्यतः विनाश का प्रतीक मानी जाती है, यहां कृपा का माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि भक्त इस प्रसाद को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और इसे अपने जीवन में सौभाग्य और रक्षा का प्रतीक मानते हैं।

इस परंपरा को लेकर कई बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोग इसे भ्रम या किसी विशेष तकनीक का परिणाम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन और पुजारी वर्ग का कहना है कि यह कोई प्रदर्शन या प्रयोग नहीं, बल्कि शुद्ध धार्मिक परंपरा है, जो सदियों से बिना किसी बदलाव के चली आ रही है। यहां न तो कोई रासायनिक सुरक्षा होती है और न ही कोई चाल। जो कुछ होता है, वह पूरी श्रद्धा और साधना के साथ होता है।

मां कामाख्या मंदिर की यह परंपरा भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर देती है। दूर-दूर से आए श्रद्धालु जब यह दृश्य देखते हैं, तो उनके मन में देवी के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। खासकर तांत्रिक साधना से जुड़े लोग इस प्रसाद को विशेष महत्व देते हैं।

यह भी माना जाता है कि जो पुजारी इस सेवा में तनिक भी अहंकार या भय ले आता है, वह इस कार्य के योग्य नहीं रह जाता। यहां केवल वही व्यक्ति यह सेवा कर सकता है, जो स्वयं को पूरी तरह देवी को समर्पित कर चुका हो। यही कारण है कि इस परंपरा को शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मां कामाख्या की कृपा को पाने के लिए यहां शक्ति से अधिक श्रद्धा को महत्व दिया जाता है।

कामाख्या मंदिर की यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि आस्था केवल आंख मूंदकर विश्वास करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, संयम और आत्मशुद्धि की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है। जब साधक अपने भीतर की दुर्बलताओं को जीत लेता है, तभी वह बाहरी भय से मुक्त हो पाता है। खौलते तेल में हाथ डालने का यह दृश्य उसी आंतरिक विजय का बाहरी रूप माना जाता है।

आज के आधुनिक युग में, जहाँ हर चीज को तर्क और प्रमाण के तराजू पर तौला जाता है, वहां मां कामाख्या मंदिर जैसी परंपराएं यह याद दिलाती हैं कि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। यह मंदिर विज्ञान और आस्था के बीच खड़ी उस रेखा पर स्थित है, जहाँ दोनों एक-दूसरे को चुनौती भी देते हैं और पूरक भी बनते हैं।

अंततः मां कामाख्या मंदिर की यह चमत्कारी परंपरा केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह संदेश है कि जब आस्था पूर्ण होती है, जब साधना निष्काम होती है और जब समर्पण अहंकार से मुक्त होता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। महानिर्मल्य का प्रसाद उसी दिव्य अनुभव का प्रतीक है, जो यह बताता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर से प्रकट होती है, और जब वह प्रकट होती है, तो अग्नि भी भक्त को स्पर्श नहीं कर पाती।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिलों के प्रशासनिक तंत्र को स्थानीय प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश दिए

▶▶ जनवरी - 2026 के राज्य स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में 110 प्रस्तुतियां, जिला स्वागत कार्यक्रम में 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रम में 2,565 सहित कुल 4,057 प्रस्तुतियों पर कार्रवाई की गई

▶▶ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की किसानों और सामान्य नागरिक परिवारों की समस्याओं के समाधान के प्रति विशिष्ट संवेदनशीलता

▶▶ डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने के आदेश दिए

▶▶ बोटाद जिले में गांव के तालाब की पाल की अधिक ऊंचाई के कारण डूब में जा रही किसानों की 500 बीघा भूमि तथा आवागमन के रास्ते के संबंध में त्वरित समाधान के निर्देश

▶▶ सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के गिराए गए जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के शीघ्र निर्माण के लिए गुजरात हाउसिंग बोर्ड को दिशानिर्देश

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी-2026 के राज्य स्वागत में आई प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण, ड्रेनेज और नालों में किए गए अवैध अतिक्रमण, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित राज्य स्वागत कार्यक्रम की प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित 'स्वागत ऑनलाइन' जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जनवरी-2026 के राज्य-स्वागत में राज्य भर से 110 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, जिला स्वागत कार्यक्रम की 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रमकी 2,565 प्रस्तुतियों/प्रश्नों के संदर्भ में भी जिला एवं तहसील स्तर पर समाधान की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में डभोई तथा बोटाद जिलों के किसानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों तथा सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रश्न की प्रस्तुति पर उन्होंने त्वरित एवं संवेदनशील प्रतिसाद दिया।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिए कि डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण 33 किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि की फसलों को नुकसान न हो तथा भूमि खराब न हो, इसके लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने और नगरपालिका का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सुचारु रूप से कार्य करे तथा किसानों की इस दीर्घकालीन समस्या का समाधान हो।

मुख्यमंत्री के समक्ष बोटाद जिले के किसानों ने यह प्रस्तुति रखी कि गांव के तालाब की पाल की ऊंचाई बढ़ाने के परिणामस्वरूप 42 किसानों की लगभग 500 बीघा भूमि डूब में चली जाती है तथा खेतों में आवागमन का मार्ग बंद हो गया है। श्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत किसान हितोन्मुखी निर्णय लेकर इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए।

राज्य स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों के इन प्रश्नों के अतिरिक्त, सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जिन जर्जर मकानों को गिरा दिया गया है, उनके स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रस्तुति भी लाभार्थियों द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों के संदर्भ में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को नए आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

जनवरी -2026 के इस राज्य स्वागत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव श्री अजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री डी. के. पारेख, श्री राकेश व्यास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी पर हुए अत्याचार मामले में AAP प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी की प्रतिक्रिया

▶▶ शंकराचार्य पर हुआ अत्याचार BJP द्वारा हिंदू समाज और सनातन धर्म के अपमान के समान : इसुदान गढ़वी

▶▶ हिंदू समाज और आम आदमी पार्टी शंकराचार्य पर हुए हमले का समर्थन नहीं करती : इसुदान गढ़वी

▶▶ भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सरकारी तंत्र द्वारा हिंसा और दबाव करती है : इसुदान गढ़वी

▶▶ शंकराचार्य के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी की कानूनी कार्रवाई की मांग : इसुदान गढ़वी

▶▶ भाजपा पार्टी नहीं, सर्टिफिकेट बेचने वाली कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है : इसुदान गढ़वी

▶▶ शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना सनातन परंपरा का अपमान : इसुदान गढ़वी

▶▶ शंकराचार्य पर हुए अत्याचार मुद्दे पर RSS-VHP-बजरंग दल से आवाज उठाने की इसुदान गढ़वी की अपील

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी पर हुए अत्याचार मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, एक कॉर्पोरेट कंपनी है और सबको सर्टिफिकेट बेचने का ठेका ले लिया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गत 18/01/2026 को जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी और उनके शिष्यों पर हुआ अत्याचार हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है। पुलिस और प्रशासन द्वारा शंकराचार्य और उनके शिष्यों को स्नान करने से रोका गया, पालकी रोकी गई, तथा उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर जो अत्याचार किया गया है, उससे सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ यह अत्याचार केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज और सनातन परंपरा के सर्वमान्य मूल्यों पर किया गया घोर प्रहार है। भाजपा अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है। भाजपा गायमाता, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने लगी है। शंकराचार्य से भी हिंदू आस्था का सर्टिफिकेट मांगते हैं ? आप कौन हैं? आप अपने राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दें। आम आदमी पार्टी ने शंकराचार्य के समर्थन में विभिन्न जगहों पर विरोध दर्ज कराया है।

AAP नेता इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि RSS, बजरंग दल, VHP से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे शंकराचार्यों पर भाजपा अत्याचार कर रही है, तब आपको भी एकजुट होकर इस शंकराचार्यजी के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए। आज एक शंकराचार्य हैं, कल दूसरे आएंगे, फिर हम सभी को भी हिंदुओं का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। यह केवल शंकराचार्य पर नहीं, हमारी हिंदू आस्था पर ठेस पहुंची है, आने वाली पीढ़ी पर भी ठेस पहुंची है। सभी सामाजिक संगठनों, साधु-संतों, कलाकारों, सनातन धर्म मानने वाले सभी से निवेदन करता हूं कि शंकराचार्यजी के समर्थन में हम सभी आवाज उठाएं।

रणोत्सव में सखी क्राफ्ट बाजार : एक महीने में 5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री

अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों ने ली मुलाकात, 330 स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं के लिए 100 स्टॉल्स की व्यवस्था

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विभिन्न पहलें की जा रही हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत इस वर्ष कच्छ के रणोत्सव में 4 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सखी क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। इस बाजार में स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विशाल डोम में 100 स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है। रणोत्सव में आने वाले पर्यटकों में सखी क्राफ्ट बाजार आकर्षण का केन्द्र बना है और अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। इस क्राफ्ट बाजार में 330 स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं को अलग-अलग चरणों में स्टॉल दिए जा रहे हैं, जिसमें गुजरात सहित देशभर से अन्य राज्यों की महिलाएँ भी शामिल हुई हैं। क्राफ्ट बाजार की मुलाकात पर्यटकों के लिए यादगार स्मृति बनी है। क्राफ्ट बाजार के साथ लाइव संगीत कार्यक्रमों का आयोजन तथा कैफेटेरिया भी बनाया गया है। हस्तकला तथा हथकरघा से लेकर मिट्टी के बर्तनों, ज्वैलरी तथा होम डेकोर सहित पैकेज फूड की भी यहाँ बिक्री हो रही है। इस क्राफ्ट बाजार में परंपरागत हस्तकला तथा आधुनिक डिजाइन का अनूठा संयोजन देखने को मिल रहा है। अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों ने इस सखी क्राफ्ट बाजार की मुलाकात ली है।

गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सखी मंडल की बहनों के लिए हर वर्ष मार्केटिंग के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर के 2 सरस मेलों तथा क्षेत्रीय स्तर के 10-12 सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसमें वृद्धि कर शॉपिंग फेस्टिवल, बड़े मॉडल में सखी मार्केट, फ्ली मार्केट, स्वदेशी मेलों तथा पर्यटन के कार्यक्रमों में भी सखी मंडलों के लिए वस्तुओं की बिक्री एवं ब्रैंडिंग की व्यवस्था की गई है।

अहमदाबाद- मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालनीक कारणों ट्रेन संख्या 12933 मुंबई सेंट्रल–वटवा एवं ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया जा रहा है। दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तकइस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान मुंबई सेंट्रल (MMCT) के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस (BDTS) किया जाएगा।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे समाप्त होगी। अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान का समय यथावत रहेगा। ट्रेनों के ठहराव, समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

26 जनवरी से 07 मार्च तक अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच रेक के साथ संचालित होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से 4 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दिनांक 26 जनवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक वर्तमान 16 कोचों के स्थान पर 20 कोच (20 coach Rake) के साथ संचालित की जाएगी। इस वृद्धि के अंतर्गत मौजूदा C14 कोच की क्षमता 44 सीटों से बढ़ाकर 78 सीटें की जा रही है। इसके अतिरिक्त चार नए एसी चेयर कार कोच C15, C16, C17 (प्रत्येक 78 सीटें) तथा C18 (44 सीटें) ट्रेन संरचना में जोड़े जा रहे हैं। इस तरह इस ट्रेन में 278 यात्री अधिक यात्रा कर सकेंगे। पश्चिम रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है।

पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत,रेलवे द्वारा सुधारकार्य प्रगति पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर प्रतापनगर–एकतानगर खंड पर संरक्षा में वृद्धि एवं ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं।इसी क्रम में डभोई के पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग यानि समपार फाटक संख्या 20 पर एक रोड ओवर ब्रिज (ROB)का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु रेलवे द्वारा एक डाइवर्जन रोड विकसित की गई है। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संघटनों द्वारा इस लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजाद के लिए डाइवर्जन रोड को और चौड़ा करने की मांग पर अमल करते हुए वडोदरा मंडल द्वारा तेज गति से कार्य शुरू कर दिए है।

LC-20 (पलासवाड़ा) लेवल क्रॉसिंग पर वडोदरा की ओर जाने वाले मार्ग के एग्जिट पर स्थित स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है, जिससे वाहनों के रुकने का समय कम हुआ है। इसी प्रकार, डभोई की ओर से आने वाली पुरानी सड़क पर भी स्पीड ब्रेकर को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क की खराब एवं ऊबड़-खाबड़ सतह को दुरुस्त करते हुए पुनः डामरीकरण किया गया है।

पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर पहले लिफ्टिंग बैरियर (बूम) की लंबाई मात्र 6.50 मीटर थी,जिसे अब वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग तथा गुजरात राज्य सरकार के सड़क एवं भवन (R&B) विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के उपरांत बढ़ाकर 8.20 मीटर कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब डभोई एवं वडोदरा दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए पृथक-पृथक लगभग 8.00 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गुजरात राज्य सरकार के R&B विभाग द्वारा अप्रोच रोड को और चौड़ा करने का कार्य भी प्रगति पर है। चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रेलवे द्वारा सड़क के किनारे 100 मीटर एवं 200 मीटर की दूरी पर लेवल क्रॉसिंग संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे,जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही,दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से हाइट गेज पर भी पेंटिंग की गई है।

वडोदरा मंडल द्वारा उठाए गए इन समन्वित और सुधारात्मक कदमों से आने वाले दिनों में पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर यातायात जाम की समस्या से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन की फियो के यूनियन बजट 2026 की सिफारिशें

(जीएनएस)। 1.कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के मुद्दों पर ध्यान दें

प्रस्तावः बजट में इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जहाँ कच्चे माल, कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी तैयार माल की तुलना में ज़्यादा होती है। फियो निर्यात पर ध्यान देने वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य इनपुट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज़ करने और कम करने की सिफारिश करता है ताकि इनपुट कॉस्ट तैयार प्रोडक्ट ड्यूटी के साथ अलाइन हो जाए।

औचित्यः एक इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भारतीय निर्यातकों की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफी कम कर देता है और जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज़रिए कम वर्किंग कैपिटल को लॉक कर देता है। कई सेक्टर्स को इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक यार्न और फाइबर पर तैयार फैब्रिक और गारमेंट्स की तुलना में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल वैल्यू चेन पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह, पीसीबी, कनेक्टर और सब-असेंबली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इम्पोर्टेड तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा नहीं मिलता। केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर में, बेसिक रॉ केमिकल और पॉलीमर पर अक्सर डाउनस्ट्रीम फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। लेदर और फुटवियर सेक्टर को भी इम्पोर्टेड फिनिश्ड फुटवियर के मुकाबले कंपोनेंट और एक्सेसरीज़ जैसे इनपुट पर ज़्यादा ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। रॉ मटीरियल पर ड्यूटी कम करके या रीस्ट्रक्चर करके इन गड़बड़ियों को ठीक करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, वर्किंग कैपिटल का दबाव कम होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होगी।

2.शिपिंग सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में इंडियन ग्लोबल-स्केल शिपिंग लाइनों के डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड पॉलिसी और फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, जिसमें लॉन्ग-टर्म फाइनेंस तक एक्सेस, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सपोर्टिव रेगुलेटरी उपाय शामिल हैं।

औचित्यः फॉरेन शिपिंग लाइनों पर इंडिया की भारी डिपेंडेंस एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ्रेट कॉस्ट, सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रेट में उतार-चढ़ाव का सामना कराती है। मज़बूत इंडियन शिपिंग कैरियर की कमी इंडिया की ट्रेड रेजिलिएंस और बारगेनिंग पावर को कमज़ोर करती है। इंडियन शिपिंग लाइनों को डेवलप करने से फ्रेट कॉस्ट काफी कम हो सकती है, रिलायबिलिटी बेहतर हो सकती है और लॉजिस्टिक्स पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पक्का हो सकता है। अनुमान है कि भारत एक मज़बूत घरेलू शिपिंग इकोसिस्टम के ज़रिए माल ढुलाई में सालाना USD 40-50 बिलियन बचा सकता है। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत के लंबे समय के ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा।

3.फिस्कल और टैक्स इंसेंटिव – अनुसंधान एवं विकास सपोर्ट

प्रस्तावः फियो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35(2एबी) के तहत इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए 200-250% वेटेड टैक्स डिडक्शन को फिर से शुरू करने और कंपनियों से आगे बढ़कर एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप, खासकर एमएसएमई को भी शामिल करने की सिफारिश करता है।

औचित्यः पहले, 200% वेटेड डिडक्शन ने अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया है। इसके धीरे-धीरे कम होने से भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम ऐसे समय में कमज़ोर हुआ है जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन तेज़ हो रहा है। अभी, 38 ओईसीडी देशों में से 35 अनुसंधान एवं विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव देते हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। 200% डिडक्शन देने से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़े इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। नॉन-कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को एलिजिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और अक्सर बिना फिस्कल सपोर्ट के अनुसंधान एवं विकास में इन्वेस्ट करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी की कमी होती है।

4.ओवरसीज़ मार्केटिंग के लिए टैक्स सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में ओवरसीज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर, बायर मीट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर होने वाले खर्च के लिए 200% टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिससे खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को फायदा हो।

औचित्यः कॉम्पिटिशन करने वाले एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तुलना में ग्लोबल मार्केट में भारत के सामान और सर्विस अभी भी ठीक से नहीं दिखाए जाते हैं। ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर्स को—खासकर एमएसएमई को—नए मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने से रोकती है। बढ़ी हुई टैक्स डिडक्शन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देगी और साथ ही असरदार फिस्कल बोझ भी कम करेगी। इस कदम से ब्रांड की विज़िबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लंबे समय तक ट्रेड सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी।

5.नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स का विस्तार

प्रस्तावः फियो प्रस्ताव करता है कि नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सेक्शन 115 बीएबी के तहत 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स दर को 31 मार्च, 2024 की पिछली कट-ऑफ तारीख से कम से कम पांच साल और बढ़ाया जाए।

औचित्यः ऐसे समय में जब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग निवेश और सप्लाई-चेन रीलोकेशन के लिए ज़ोरदार मुकाबला कर रहा है, इस रियायती टैक्स व्यवस्था के खत्म होने से मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत का आकर्षण कम हो जाता है। इस योजना को बढ़ाने से पॉलिसी में निश्चितता आएगी, निवेश पर टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर होगा, और सरकार के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट-आधारित विकास के उद्देश्यों को मज़बूती मिलेगी। यह उपाय एक सुसंगत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय ढांचा बनाकर, नए पूंजी निवेश, रोज़गार सृजन और भारत में उच्च मूल्य-वर्धित मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करके पीएलआई योजनाओं का भी पूरक होगा।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1) ट्रेन संख्या 09035/09036 बांद्रा टर्मिनस–उधना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09035 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 09:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 15:05 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 30 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09036 उधना–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को उधना से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वानगांव, दहाणू रोड, घोलवड, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भीलाड, करमबेली, वापी, वलसाड, बिलीमोरा तथा नवसारी स्टेशनों पर रुकेगी।

इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09035 भायंदर तथा ट्रेन संख्या 09036 अतुल, पारडी एवं उदवाडा स्टेशनों पर भी रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09561/09562 बांद्रा टर्मिनस–ओखा साप्ताहिक स्पेशल [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09561 बांद्रा टर्मिनस–ओखा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 05:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 22:50 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09562 ओखा–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को ओखा से 10:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खंभालिया तथा द्वारका स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, एसी–3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3) ट्रेन संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:00 बजे भिवानी पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09006 भिवानी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को भिवानी से 14:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 26 फरवरी, 2026 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, कोसली तथा चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09035, 09036, 09561, 09562 एवं 09005 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुली है। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद- मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालनीक कारणों से ट्रेन संख्या 12933 मुंबई सेंट्रल–वटवा एवं ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया जा रहा है। दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक इस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान मुंबई सेंट्रल (MMCT) के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस (BDTS) किया जाएगा।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे समाप्त होगी।

अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान का समय यथावत रहेगा।

ट्रेनों के ठहराव, समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

पार्सल लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए ई-ऑक्शन

अहमदाबाद मंडल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में पार्सल स्पेस लीज पर देने के लिए ई-ऑक्शन आमंत्रित किया गया है। कैटलॉग पहले ही IREPS वेबसाइट पर पब्लिश किया जा चुका है। विवरण नीचे दिया गया हैं:

कैटलॉग नंबर	कॉन्ट्रैक्ट का प्रकार	श्रेणी	ई-नीलामी की तारीख और समय
Lease-ADI-02-26	पार्सल	पार्सल-SLR	सभी लॉट के लिए ई-ऑक्शन 09.02.2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
Lease-ADI-03-26	पार्सल	पार्सल-SLR	सभी लॉट के लिए ई-ऑक्शन 10.02.2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।
Lease-ADI-04-26	पार्सल	पार्सल-SLR और पार्सल-पार्सल वैन	सभी लॉट के लिए ई-ऑक्शन 11.02.2026 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।

नोट: संभावित बोली लगाने वाले रजिस्ट्रेशन और भागीदारी के लिए IREPS **(www.ireps.gov.in)** पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल पर जा सकते हैं। लॉट-वार विवरण आगामी ई-नीलामी (जोन: पश्चिम रेलवे, यूनिट: अहमदाबाद मंडल – वाणिज्यिक) के तहत उपलब्ध हैं। प्रारंभिक कूलिंग-ऑफ अवधि 30 मिनट है। क्रमिक लॉट बंद होने का अंतराल 10 मिनट है। लॉट-वाइज़ क्लोजिंग टाइम IREPS के ई-ऑक्शन मॉड्यूल में देखा जा सकता है।

ADI 259

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

अमेजन को बचाने की साझा जंग: अवैध सोना खनन पर अंतरराष्ट्रीय शिकंजा, 200 से ज्यादा

(जीएनएस)। बोगोटा। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन को लंबे समय से जिस खामोश लेकिन विनाशकारी खतरे ने जकड़ रखा है, उसके खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई शुरू हो गई है। ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, गुयाना और सूरीनाम ने पहली बार सीमाओं से परे जाकर एक साझा अभियान चलाया, जिसमें अवैध सोना खनन से जुड़े करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर में चलाए गए इस व्यापक ऑपरेशन ने न सिर्फ संगठित पर्यावरण अपराध के नेटवर्क को झटका दिया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि अमेजन की तबाही को अब केवल एक देश की समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता।

अवैध सोना खनन पिछले कई वर्षों से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई, नदियों के जहरीले प्रदूषण और आदिवासी समुदायों के विस्थापन का बड़ा कारण बन चुका है। खनन माफिया घने जंगलों को काटकर वहां अस्थायी शिविर बनाते हैं, भारी मशीनों से जमीन खोदते हैं और सोना निकालने के लिए पारे का इस्तेमाल करते हैं। यही पारा नदियों में घुलकर मछलियों, वन्यजीवों और इंसानों तक पहुंचता है। इसका असर सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन हजारों आदिवासी परिवारों की सेहत और जीवनशैली पर भी पड़ता है, जिनका अस्तित्व नदियों और जंगलों पर निर्भर है।

इस बार की कार्रवाई इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें इंटरपोल, यूरोपीय संघ और पर्यावरण अपराध में विशेषज्ञ डच पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। चारों देशों की पुलिस और अभियोजन एजेंसियों ने एक साथ, एक ही समय पर अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की। इस तालमेल का फायदा यह हुआ कि अपराधियों को एक देश से दूसरे देश भागने का मौका नहीं मिला, जो अब तक उनकी सबसे बड़ी रणनीति रही है। सीमाओं की कमजोरी का फायदा उठाकर ये नेटवर्क सालों से कानून से बचते रहे थे।

इंटरपोल के मुताबिक, इस अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, कच्चा सोना, पारा, हथियार, मादक पदार्थ और खनन में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए। यह बरामदगी इस बात की पुष्टि करती है कि अवैध सोना खनन केवल पर्यावरण अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध का हिस्सा है, जिसका सीधा संबंध तस्करी, ड्रग्स और हथियारों के अवैध कारोबार से भी है। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि इन नेटवर्कों के तार अंतरराष्ट्रीय अपराध गिरोहों से जुड़े हुए हैं, जो सोने को काले बाजार के जरिए वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल कर देते हैं।

गुयाना और सूरीनाम में पारा तस्करी का भंडाफोड़ इस अभियान की एक और अहम उपलब्धि रहा। जांच में पता चला कि करीब 60,000 डॉलर से ज्यादा मूल्य का पारा सोलर पैनलों में छिपाकर बसों के जरिये एक देश से दूसरे देश ले जाया जा रहा था। पारा अवैध खनन का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि यह मिट्टी और पानी में घुलकर दशकों तक पर्यावरण को जहरीला बनाए रखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पारे के कारण अमेजन की कई नदियों में मछलियों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और आदिवासी इलाकों में न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। खनन स्थलों को नष्ट किया गया, सप्लाई लाइनों की पहचान की गई और उन आर्थिक स्रोतों पर भी नजर रखी जा रही है, जिनसे इस अवैध गतिविधि को फंडिंग मिलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर केवल मजदूरों या छोटे स्तर के खनिकों को पकड़ा जाए और बड़े फाइनेंसर बच निकलें, तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए इस बार जांच एजेंसियों ने मनी ट्रेल और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन पर भी खास फोकस किया है।

अमेजन को अक्सर "धरती के फेफड़े" कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। अवैध खनन से होने वाली वनों की कटाई इस संतुलन को बिगाड़ रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अमेजन का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, तो इसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मौसम चक्र पर पड़ेगा। ऐसे में यह अंतरराष्ट्रीय अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जरूरी और देर से उठाया गया कदम माना जा रहा है।

हालांकि, जानकार यह भी कहते हैं कि एक अभियान से समस्या खत्म नहीं होगी।

पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य गारंटी पूरी - इसुदान गढ़वी

▸▸ अब पंजाब के 65 लाख परिवारों को बिना शर्त और बिना भेदभाव के 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा – इसुदान गढ़वी

▸▸ जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा – इसुदान गढ़वी

▸▸ "आप" के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री विदेश में सैर-सपाटा कर रहे – इसुदान गढ़वी

▸▸ देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है – इसुदान गढ़वी

▸▸ मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य – इसुदान गढ़वी

▸▸ कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं, इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए – इसुदान गढ़वी

▸▸ सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को सुरक्षित भविष्य दे सकती है – इसुदान गढ़वी

▸▸ यह दुनिया की इकलौती स्कीम है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर और हृदय रोग का भी मुफ्त इलाज होगा – इसुदान गढ़वी

(जीएनएस)। गुजरात/अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई। इस अवसर पर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दी गई मुफ्त इलाज की गारंटी अब पूरी तरह साकार हो चुकी है। अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत के साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा एक साथ दी जा रही है।

जिन शानदार और महंगे निजी अस्पतालों में अब तक केवल अमीर लोग इलाज कराते थे, अब वहां गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी बिना पैसे के इलाज करा सकेगा। यह देश के इतिहास की पहली ऐसी योजना है, जो सच में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कुछ मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ विदेशों में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री रात-दिन जनता के लिए हेल्थ कार्ड बनाने में लगे हैं। यही फर्क है उनकी सैर-सपाटे की राजनीति और आम आदमी पार्टी की सेवा की राजनीति में। कांग्रेस और अन्य दलों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। इन पार्टियों को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता की चिंता है ताकि वे लूट सकें। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब और पंजाबियों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है।

उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने जनता की असली चिंता नहीं की। आज जो ऐतिहासिक काम पंजाब में हो रहा है, वह आज़ादी के बाद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह दौर पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

चुनावी वादों का जिक्र करते हुए इसुदान गढ़वी ने कहा कि 'केजरीवाल की गारंटी' को मज़ाक समझने वाले आज देख रहे हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज सब कुछ संभव है। सरकार ने न केवल वादे पूरे किए, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बीते चार वर्षों में 1000 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, 500 और बन रहे हैं और अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं। जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, मशीनें चालू हैं, मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं और सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से बेहतर बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन किसानों और मजदूरों के लिए वरदान है, जिन्हें बीमारी में अपनी ज़मीन, गहने और घर बेचने पड़ते थे। अब किसी को इलाज के लिए कर्ज़ या ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा सभी 65 लाख परिवारों के लिए है – अमीर-गरीब, सभी धर्मों और जातियों के लिए, बिना किसी शर्त के। न कोई कार्ड का रंग, न कोई भेदभाव। बस हेल्थ कार्ड दिखाइए और इलाज पाइए।

उन्होंने नशे और अपराध के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है। जब पंजाब के बच्चे नशे से मर रहे थे, तब विपक्ष को मानवाधिकार याद नहीं आए। आज अपराधियों पर कार्रवाई होने पर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। यह कुदरत का करिश्मा है कि आम लोगों की यह पार्टी सत्ता में आई और जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस योजना का भी विरोध करेगा, लेकिन यह योजना सबके लिए है – "आप" सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा। सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे।

अंत में इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत देश के परिवारों के भविष्य की चिंता करती है। हमें सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। जनता का विश्वास और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम, भारत का पावर ग्रिड बना दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में शामिल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के ऊर्जा क्षेत्र ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। देश का पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क अब पांच लाख सर्किट किलोमीटर के आंकड़े को पार कर चुका है, जो न केवल तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और भविष्य की जरूरतों के प्रति उसकी तैयारी को भी दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड वाले देशों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती है। 14 जनवरी को राजस्थान में भादला द्वितीय से सीकर द्वितीय सबस्टेशन के बीच 765 केवी की 628 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन के सफल संचालन के साथ यह मील का पत्थर हासिल हुआ, जिसने देश की ऊर्जा संरचना को और अधिक सशक्त बना दिया।

भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए बिजली केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, औद्योगिक प्रगति और सामाजिक बदलाव की रीढ़ है। पिछले एक दशक में जिस तरह से देश में बिजली उत्पादन और उपभोग दोनों में तेज़ी आई है, उसने ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। पांच लाख सर्किट किलोमीटर का यह नेटवर्क इस बात का प्रमाण है कि भारत ने केवल उत्पादन पर ही नहीं, बल्कि बिजली को देश के हर कोने तक पहुंचाने वाली व्यवस्था पर भी समान रूप से ध्यान दिया है।

इस नई ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से भादला, रामगढ़ और फतेहगढ़ जैसे बड़े सौर ऊर्जा परिसरों से अतिरिक्त 1,100 मेगावाट बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। राजस्थान पहले ही देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा केंद्रों में से एक बन चुका है और वहां से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा को देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए मजबूत पारेषण ढांचे की आवश्यकता थी। यह लाइन उस जरूरत को पूरा करती है और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है।

यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2014 से अब तक भारत ने उच्च-वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस अवधि में 2.09 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक 220 केवी और उससे ऊपर की पारेषण लाइनों को जोड़ा गया है, जिससे नेटवर्क की कुल क्षमता में लगभग 71.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह विस्तार केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे वह रणनीतिक सोच है, जो देश को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा की ओर ले जाना चाहती है।

रूपांतरण क्षमता में 876 जीवीए की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि भारत ने केवल लाइनों की लंबाई ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बिजली के सुचारू और सुरक्षित प्रवाह के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता पर भी गंभीरता से काम किया है। अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता के 1,20,340 मेगावाट तक पहुंचने से "एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक आवृत्ति" का सपना साकार हो सका है। इसका सीधा लाभ यह है कि अब देश के एक हिस्से में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को दूसरे हिस्से में तुरंत भेजा जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है और बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर बनती है।

यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब भारत नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत अक्सर मौसम पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनसे उत्पादित बिजली को ग्रिड में स्थिरता के साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती होती है। मजबूत और विस्तृत पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इस चुनौती का समाधान है। पांच लाख सर्किट किलोमीटर का नेटवर्क इस बात को सुनिश्चित करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जहां भी हो, उसका उपयोग देश के किसी भी हिस्से में किया जा सके।

सरकार और विद्युत मंत्रालय का ध्यान अब केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की मांगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। चल रही अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं से लगभग 40,000 सर्किट किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइनें और 399 जीवीए रूपांतरण क्षमता जुड़ने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रस्तावित अतिरिक्त परियोजनाओं से 27,500 सर्किट किलोमीटर और 134 जीवीए क्षमता और बढ़ सकती है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य ग्रिड की विश्वसनीयता को और मजबूत करना तथा नवीकरणीय ऊर्जा की अधिक से अधिक निकासी को संभव बनाना है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क का यह विस्तार भारत के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। उद्योगों के लिए निर्बाध और किफायती बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। मजबूत ग्रिड से न केवल बिजली कटौती की समस्या कम होती है, बल्कि उत्पादन लागत में भी स्थिरता आती है। इससे निवेश का माहौल बेहतर होता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा महुवा-धोला रेल खण्ड तथा भावनगर वर्कशॉप का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 22 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को भावनगर मंडल के महुवा-धोला रेल खण्ड तथा भावनगर परा स्थित ब्राडगेज वर्कशॉप का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत एवं सूक्ष्म मूल्यांकन किया। महाप्रबंधक के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष, भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अपने वार्षिक संरक्षा निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने लेवल क्रॉसिंग, महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों, अंडरब्रिज, सेक्शनल स्पीड ट्रायल, पॉइंट एवं क्रॉसिंग सहित विभिन्न संरक्षा तत्वों का गहन निरीक्षण किया तथा उन्होंने महुवा, सावरकुंडला एवं धोला स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया।

महुवा में उन्होंने रेलवे स्टेशन के अलावा लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर एवं चल टिकट निरीक्षक रनिंग रूम, सोलर इंस्टॉलेशन, रेलवे कॉलोनी इत्यादि का संरक्षा निरीक्षण किया। सावरकुंडला में इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े ओवरहेड इक्विपमेंट डिपो का निरीक्षण किया। इस सेक्शन में श्री गुप्ता ने रेलवे स्टेशन के अलावा लॉबी, रेलवे कॉलोनी तथा हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया। लीलीया मोटा-धोला खण्ड के बीच 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल रन किया गया। उन्होंने धोला में कॉलोनी, हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया। भावनगर परा स्थित ब्रॉडगेज वर्कशॉप में उन्होंने कोच सेक्शन, व्हील शॉप, एयर ब्रेक शॉप, नए बने हेरिटेज गैलरी इत्यादि का संरक्षा निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। अमरेली के माननीय सांसद श्री भरतभाई सुतरिया एवं माननीय विधायक-सावरकुंडला श्री महेशभाई लालजीभाई कसवाला एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सावरकुंडला रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक की शुभेच्छा मुलाकात हुई। इसके अलावा महुवा, सावरकुंडला, धोला एवं भावनगर परा में ट्रेड यूनियन, चेम्बर ओफ कॉमर्स, सरपंच इत्यादि ने महाप्रबंधक के साथ मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

महाप्रबंधक ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैक, समपार फाटकों तथा अन्य संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि ट्रेन सेवाएँ अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुसार संचालित की जा सकें।

भारत के कौशल भविष्य को वैश्विक उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में कौशल विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और उसे वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच के बीच हुआ ताजा समझौता केवल एक औपचारिक करार नहीं, बल्कि देश के युवा कार्यबल को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस साझेदारी का मूल उद्देश्य भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालना और उसे तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। आने वाले वर्षों में करोड़ों युवा कार्यबल में प्रवेश करने वाले हैं। यह स्थिति अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि सही कौशल और प्रशिक्षण के साथ यह युवा शक्ति भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना सकती है, और चुनौती इसलिए कि यदि यह कार्यबल आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं हुआ, तो बेरोजगारी और कौशल-असंतुलन जैसी समस्याएं गहराती चली जाएंगी। ऐसे समय में एमएसडीई और डब्ल्यूईएफ के बीच हुआ यह समझौता नीति और क्रियान्वयन, दोनों स्तरों पर एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।

इस समझौते के तहत भारत में 'स्किल्स एक्सीलरेटर' की स्थापना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की योजना है। इसका मतलब यह है कि कौशल विकास कार्यक्रम अब केवल सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें उद्योग की वास्तविक मांग, तकनीकी बदलाव और वैश्विक रोजगार बाजार की जरूरतों से सीधे जोड़ा जाएगा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वह सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों का सामना कर सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन जॉब्स, डेटा एनालिटिक्स और उभरते क्षेत्रों में कौशल निर्माण पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।

विश्व आर्थिक मंच की भागीदारी इस पहल को वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता से समृद्ध करती है। डब्ल्यूईएफ वर्षों से दुनिया भर में सरकारों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर भविष्य की नौकरियों, कौशल अंतर और कार्यबल के बदलाव पर काम करता रहा है। भारत के साथ यह साझेदारी न केवल वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने का अवसर देगी, बल्कि भारतीय मॉडल को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी। इससे भारत की कौशल नीति एकतरफा नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक संवाद और सहयोग का हिस्सा बनेगी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी का यह कहना कि भारत का कौशल तंत्र अब भविष्य की कार्य-आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक सहयोग के साथ संगठित रूप ले चुका है, इस पहल की गंभीरता को दर्शाता है। उनका बयान इस बात का संकेत है कि सरकार कौशल विकास को केवल सामाजिक योजना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार मान रही है। आज जब दुनिया भर में नौकरियों की प्रकृति तेजी से बदल रही है, तब भारत का समय से पहले इस दिशा में कदम बढ़ाना उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है।

इस समझौते का एक अहम पहलू यह भी है कि इससे शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने में मदद मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि डिग्री और डिप्लोमा रखने के बावजूद युवाओं में उद्योग के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल की कमी रह जाती है। स्किल्स एक्सीलरेटर के माध्यम से पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, लचीला और उद्योग-संगत बनाया जा सकता है। इससे न केवल रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो कई देश अपने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने में पीछे छूट रहे हैं। ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के कारण पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं और नई तरह की नौकरियां उभर रही हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह केवल सस्ते श्रम का केंद्र न बने, बल्कि कुशल और उच्च मूल्य वाले कार्यबल के रूप में अपनी पहचान बनाए। एमएसडीई और डब्ल्यूईएफ की यह साझेदारी इसी दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 1272 रुपये, चांदी वायदा 10190 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा 89 रुपये लुढ़का

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 346944.33 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 96389.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 250535.62 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 41400 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 7221.34 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 82052.01 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 151557 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153784 रुपये और नीचे में 148777 रुपये पर पहुंचकर, 152862 रुपये के पिछले बंद के सामने 1272 रुपये या 0.83 फीसदी गिरकर 151590 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 2720 रुपये या 2.11 फीसदी औंधकर 126300 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 392 रुपये या 2.44 फीसदी औंधकर 15666 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 152347 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154067 रुपये और नीचे में 148741 रुपये पर पहुंचकर, 1641 रुपये या 1.07 फीसदी औंधकर 151700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 152804 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156144 रुपये और नीचे में 149951 रुपये पर पहुंचकर, 154588 रुपये के पिछले बंद के सामने 1984 रुपये या 1.28 फीसदी औंधकर 152604 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 319843 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 325602 रुपये और नीचे में 305449 रुपये पर पहुंचकर, 318492 रुपये के पिछले बंद के सामने 10190 रुपये या 3.2 फीसदी घटकर 308302 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 10264 रुपये या 3.18 फीसदी लुढ़ककर 312699 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 10089 रुपये या 3.12 फीसदी औंधकर 312873 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 96389.85 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 250535.62 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 82052.01 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 41400 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 6080.74 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 25.1 रुपये या 1.96 फीसदी गिरकर 1254.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 55 पैसे या 0.18 फीसदी की नरमी के साथ 311.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.05 रुपये या 0.33 फीसदी औंधकर 314 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी की नरमी के साथ 190.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8249.80 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5590 रुपये के भाव पर खूलकर, 5600 रुपये के दिन के उच्च और 5469 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 89 रुपये या 1.6 फीसदी गिरकर 5480 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 88 रुपये या 1.58 फीसदी गिरकर 5481 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 456 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 504.7 रुपये और नीचे में 456 रुपये पर पहुंचकर, 438.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 65.8 रुपये या 14.99 फीसदी बढ़कर 504.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 65.8 रुपये या 14.98 फीसदी बढ़कर 505 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 950.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 30 पैसे या 0.03 फीसदी के सुधार के साथ 959 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 43794.21 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 38257.79 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5461.18 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 286.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 33.79 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 292.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 602.16 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 7639.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19175 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 92440 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31381 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 426384 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61177 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13982 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 37665 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 106482 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17686 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26943 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 41898 पॉइंट पर खूलकर, 41998 के उच्च और 40905 के नीचले स्तर को छूकर, 766 पॉइंट घटकर 41400 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 39 रुपये की गिरावट के साथ 201.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 525 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.7 रुपये की बढ़त के साथ 15 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 985 रुपये की गिरावट के साथ 1369 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5784.5 रुपये की गिरावट के साथ 7630 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.07 रुपये की गिरावट के साथ 1.26 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 28 पैसे की नरमी के साथ 0.32 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 41 रुपये की बढ़त के साथ 257.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 25.4 रुपये की गिरावट के साथ 3.4 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 474.5 रुपये की बढ़त के साथ 1946.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2295 रुपये की बढ़त के साथ 7777 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.78 रुपये की बढ़त के साथ 7.78 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 29 पैसे की नरमी के साथ 0.02 रुपये हुआ।